SHODHPATRA: INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE AND HUMANITIES
E-ISSN: 3048-6041 | Volume- 3, Issue- 6 | June 2026

वर्तमान अमेरिका-ईरान संघर्ष (2026) का चीन की बेल्ट एंड रोड पहल पर पड़ने वाले भू-रणनीतिक और आर्थिक प्रभावों का विश्लेषण

चन्द्र प्रकाश पाठक
शोध छात्र, राजनीति विज्ञान विभाग , महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी (उ. प्र.)

शोध-सार

भारत सहित समूचा विश्व वर्तमान में अमेरिका–ईरान संघर्ष से उत्पन्न गहन भू-राजनीतिक एवं भू-आर्थिक अस्थिरता का सामना कर रहा है। इस संघर्ष ने केवल मध्य पूर्व की क्षेत्रीय सुरक्षा को ही प्रभावित नहीं किया है, बल्कि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति, अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक मार्गों तथा विश्व अर्थव्यवस्था की स्थिरता पर भी व्यापक प्रभाव डाला है। विशेष रूप से होर्मुज जलडमरूमध्य में उत्पन्न संकट ने वैश्विक तेल एवं गैस आपूर्ति को गंभीर रूप से प्रभावित किया है, जिसके परिणामस्वरूप ऊर्जा कीमतों में तीव्र उतार-चढ़ाव, आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान तथा विश्वव्यापी आर्थिक अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हुई है। यह संकट उन सामरिक समुद्री मार्गों की संवेदनशीलता को भी रेखांकित करता है, जिन पर वैश्विक व्यापार का बड़ा भाग निर्भर करता है। इस परिवर्तित परिदृश्य में प्रमुख शक्तियाँ जैसे चीन, रूस, यूरोपीय संघ और भारत—अपनी ऊर्जा सुरक्षा, व्यापारिक रणनीतियों तथा कनेक्टिविटी परियोजनाओं का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए बाध्य हुई हैं। विशेष रूप से चीन की बेल्ट एंड रोड पहल (BRI), जिसका उद्देश्य एशिया, यूरोप और अफ्रीका के मध्य आर्थिक एवं अवसंरचनात्मक संपर्क को सुदृढ़ करना है, इस संकट से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुई है। समुद्री मार्गों की बढ़ती असुरक्षा ने चीन को वैकल्पिक भूमि-आधारित संपर्क मार्गों और यूरेशियन कनेक्टिविटी नेटवर्कों की ओर अधिक ध्यान देने के लिए प्रेरित किया है। साथ ही, यह परिस्थिति चीन की दीर्घकालिक 'मलक्का दुविधा' को भी पुनः प्रासंगिक बनाती है। इसी पृष्ठभूमि में यह अध्ययन अमेरिका–ईरान संघर्ष और होर्मुज संकट के संदर्भ में चीन की बेल्ट एंड रोड पहल पर पड़ने वाले भू-आर्थिक, सामरिक तथा राजनीतिक प्रभावों का समग्र एवं विश्लेषणात्मक मूल्यांकन प्रस्तुत करता है।

मुख्य शब्द - बेल्ट एंड रोड पहल (BRI), अमेरिका–ईरान संघर्ष, भू-रणनीति, ऊर्जा सुरक्षा, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला।

परिचय

अमेरिका और ईरान के मध्य भू-राजनीतिक शत्रुता की जड़ें ऐतिहासिक रूप से 1953 के तख्तापलट (जिसमें सीआईए ने लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित प्रधान मंत्री मोहम्मद मोसादेघ को अपदस्थ किया था) और 1979 की इस्लामी क्रांति तथा उसके बाद के बंधक संकट तक जाती हैं । इस प्रकार यह युद्ध कई वर्षों के कूटनीतिक गतिरोध, परमाणु संवर्धन को लेकर विवादों, आर्थिक प्रतिबंधों और क्षेत्रीय छद्म युद्धों (हुती, हिज़्बुल्लाह) की एक हिंसक परिणति है । इसी प्रकार ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को लेकर पश्चिमी शक्तियों में ऐतिहासिक अविश्वास और कूटनीतिक गतिरोध की जड़ें अत्यंत गहरी रही हैं। वर्ष 2018 में अमेरिका द्वारा परमाणु समझौते (JCPOA) से एकतरफा हटने के पश्चात, दोनों राष्ट्रों के मध्य रणनीतिक वैमनस्य एक विस्फोटक चरण में पहुँच गया था। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) की समकालीन रिपोर्टों ने यह खुलासा भी किया था कि ईरान ने अपनी अभेद्य भूमिगत सुविधाओं में अत्यधिक

Published: 17 June 2026
DOI: https://doi.org/10.70558/SPIJSH.2026.v3.i6.45793
Copyright © 2026 The Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).

संवर्धित यूरेनियम का विशाल भंडार संकलित कर लिया है। इसके अतिरिक्त, तेहरान द्वारा परमाणु ठिकानों के निरीक्षण में निरंतर बाधा उत्पन्न करने और अमेरिका तक मार करने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल तकनीक के विकास ने वाशिंगटन को सैन्य कार्रवाई के लिए उत्प्रेरित किया। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी इसी परमाणु पुनरुद्धार को युद्ध के प्राथमिक *"कैसस बेली"* के रूप में प्रस्तुत किया था।

वर्तमान युद्ध की तात्कालिक पृष्ठभूमि 2024 और 2025 की घटनाओं में निहित है। 2024 के इज़राइल-हमास युद्ध के दौरान, इज़राइल ने ईरान के क्षेत्रीय प्रभाव को काफी हद तक कम कर दिया था, जिसमें लेबनान में हिज़्बुल्लाह को कमज़ोर करना और सीरिया में बशर अल-असद की ईरान-समर्थक सरकार का पतन शामिल था । जून 2025 में इज़राइल और ईरान के बीच 12-दिवसीय युद्ध हुआ, जिसमें इज़राइल ने ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों को पंगु बना दिया और अमेरिका ने फोर्डो, नतान्ज़ और इस्फहान में स्थित भूमिगत परमाणु सुविधाओं पर 'बंकर बस्टर' (GBU-57 A/B) बमों से हमला किया । इन हमलों और कड़े अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण ईरान की अर्थव्यवस्था बर्वाद हो गई, जिसके परिणामस्वरूप 28 दिसंबर 2025 को ईरान में व्यापक राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन भड़क उठे । इन प्रदर्शनों को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प का खुला समर्थन प्राप्त था, जिन्होंने चेतावनी दी थी कि यदि ईरान ने प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग किया तो अमेरिका हस्तक्षेप करेगा । इसके बावजूद, 8 जनवरी 2026 को ईरानी सुरक्षा बलों ने एक क्रूर दमन चक्र चलाया, जिसमें ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार लगभग 30,000 लोग मारे गए । इस घटना ने अमेरिका को मध्य पूर्व में 2003 के इराक आक्रमण के बाद से अपना सबसे बड़ा सैन्य जमावड़ा करने का अवसर प्रदान किया ।

'ऑपरेशन एपिक फ्यूरी' के तहत ईरान पर इन हमलों का उद्देश्य ईरानी नेतृत्व और उसके सैन्य बुनियादी ढांचे को पूरी तरह से नष्ट करना था। इस प्रारंभिक हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई और दर्जनों अन्य उच्च पदस्थ अधिकारी मारे गए । नेतृत्व विहीन होने के बावजूद, ईरान की राजनीतिक प्रणाली ध्वस्त नहीं हुई; मोजतबा खामेनेई के नेतृत्व में कट्टरपंथियों ने तुरंत सत्ता पर नियंत्रण कर लिया और अमेरिका तथा इज़राइल के खिलाफ एक अत्यधिक आक्रामक ' असममित युद्ध' की रणनीति अपनाई । ईरान ने 'क्षैतिज विस्तार' की रणनीति के तहत होर्मुज जलडमरूमध्य में वाणिज्यिक नौवहन को निशाना बनाया, जो वैश्विक समुद्री तेल व्यापार का लगभग 20% (औसतन 20.3 मिलियन बैरल पेट्रोलियम और कच्चा तेल प्रतिदिन) वहन करता है । अमेरिका ने मई में 'प्रोजेक्ट फ्रीडम' के तहत वाणिज्यिक जहाजों को एस्कॉर्ट करने का प्रयास किया, जिससे सीधे सैन्य टकराव हुए । इस नाकेबंदी के कारण कच्चे तेल की कीमतें 120 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गईं, जिससे एशिया और यूरोप में मुद्रास्फीति, मंदी और आपूर्ति श्रृंखला के व्यवधान का खतरा अभूतपूर्व रूप से बढ़ गया । 2026 के इस युद्ध ने महान शक्तियों के बीच 'समुद्री शक्ति' (थेयर महान का सिद्धांत) और 'भूमि शक्ति' (मैकिन्डर का सिद्धांत) की पुरानी भू-राजनीतिक बहस को पुनर्जीवित कर दिया है । होर्मुज जलडमरूमध्य के बंद होने से यह सिद्ध हो गया है कि वैश्वीकरण का युग समाप्त हो रहा है और वैश्विक अर्थव्यवस्था एक महान शक्ति 'स्टेबलाइजर' के अभाव में अत्यधिक असुरक्षित है । इस स्थिति ने चीन और रूस को अमेरिकी नौसैनिक प्रभुत्व और आर्थिक दबाव को दरकिनार करने के लिए यूरेशिया के आंतरिक महाद्वीपीय मार्गों को मजबूत करने के लिए तत्काल प्रेरित किया है।

यह अब एक निर्विवाद तथ्य बन चुका है कि होर्मुज जलडमरूमध्य में व्याप्त संकट, समुद्री नाकेबंदी और वाणिज्यिक पोतों पर निरंतर होते प्रहारों ने वैश्विक राजनीतिक अर्थव्यवस्था के बुनियादी ढाँचे को रूपांतरित कर दिया है। आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापारिक मार्ग पहले की तुलना में कहीं अधिक असुरक्षित और चुनौतीपूर्ण बने रहने की संभावना है। उल्लेखनीय है कि वैश्विक तेल व्यापार का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा और एशियाई देशों की ऊर्जा आपूर्ति का एक बड़ा भाग इसी सामरिक मार्ग पर निर्भर है। परिणामस्वरूप, इस क्षेत्र की अस्थिरता न केवल क्षेत्रीय सुरक्षा को खतरे में डालती है, बल्कि यह विश्व की ऊर्जा सुरक्षा, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं और वित्तीय स्थिरता

के लिए भी एक प्रत्यक्ष संकट है। होर्मुज के वर्तमान घटनाक्रम ने इस वास्तविकता को पुनः रेखांकित किया है कि समुद्री चोकपॉइंट्स—विशेष रूप से होर्मुज, बाब-अल-मंदेब, मलक्का और स्वेज नहर—अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के सबसे नाज़ुक बिंदु हैं, जिनकी सुरक्षा की कोई भी स्थायी गारंटी भविष्य में संभव नहीं दिखती।

चीन की बेल्ट एंड रोड पहल (BRI) पर रणनीतिक प्रभाव: एक समग्र विश्लेषण

चीन की आर्थिक शक्ति और ऊर्जा सुरक्षा पारंपरिक रूप से मलक्का और होर्मुज जैसे समुद्री जलडमरूमध्यों पर टिकी रही है। वर्तमान संकट ने बीजिंग की इस रणनीतिक कमजोरी को उजागर कर दिया है, जिससे 'मलक्का दुविधा' अब और अधिक गंभीर रुप से 'होर्मुज दुविधा' का रूप ले चुकी है। इसके परिणामस्वरूप, चीन ने अपनी 'बेल्ट एंड रोड पहल' (BRI) के तहत समुद्री रेशम मार्ग के बजाय महाद्वीपीय सिल्क रोड आर्थिक बेल्ट पर अपना ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया है। इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य युद्ध या अमेरिकी नाकेबंदी जैसी स्थितियों में अपनी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित और निरंतर बनाए रखना है।

होर्मुज जलडमरूमध्य में युद्ध-जोखिम बीमा की लागत संघर्ष से पूर्व के 0.12% से बढ़कर 5% तक पहुंचने के कारण समुद्री परिवहन अधिकांश ऑपरेटरों के लिए आर्थिक रूप से अव्यवहार्य हो गया है। इसके प्रत्युत्तर में, चीन ने मध्य एशिया के माध्यम से ईरान तक 10,400 km लंबे महाद्वीपीय रेल ब्रिज को पूरी तरह से सक्रिय कर दिया है। यह विशाल रेल नेटवर्क पश्चिमी चीन से शुरू होकर कज़ाकिस्तान के खोरगोस गेटवे में प्रवेश करता है। वहां से यह पूर्व सोवियत रेल नेटवर्क का उपयोग करते हुए अल्माटी , अरीस जंक्शन होते हुए उज़्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद पहुंचता है। इसके बाद यह मार्ग ऐतिहासिक शहरों समरकंद और बुखारा से गुजरते हुए तुर्कमेनिस्तान के काराकुम रेगिस्तान को पार करता है और अंततः ईरान की सीमा में प्रवेश कर मशहद और तेहरान तक पहुँचता है। यद्यपि रेल परिवहन की मात्रा एक सुपरटैंकर की तुलना में कम होती है, लेकिन भू-राजनीतिक और सैन्य दृष्टि से, यह मार्ग अमेरिकी नौसेना के अंतरविरोध से पूर्णतः सुरक्षित है। चीन ने इस मार्ग के माध्यम से होने वाले ऊर्जा और वस्तुओं के व्यापार को युआन में मूल्यवर्गित करना शुरू कर दिया है। चीनी रणनीति के इस घटक का उद्देश्य न केवल वाशिंगटन द्वारा लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों की प्रभावकारिता को समाप्त करना है, बल्कि ऊर्जा के अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अमेरिकी डॉलर के पारंपरिक वर्चस्व को रणनीतिक रूप से चुनौती देना भी है।

इस महाद्वीपीय रणनीति को मजबूत करने में पाकिस्तान ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 25 अप्रैल 2026 को, पाकिस्तान के वाणिज्य मंत्रालय ने "पारगमन व्यापार आदेश 2026" जारी किया, जिसने कराची, पोर्ट कासिम और ग्वादर से ईरान के गबद और ताफ्तान सीमा क्रॉसिंग तक सड़क मार्ग को आधिकारिक रूप से खोल दिया। ग्वादर-गबद कॉरिडोर यात्रा के समय को 16-18 घंटे से घटाकर मात्र दो से तीन घंटे कर देता है, जिससे शिपिंग की तुलना में परिवहन लागत में 45 से 55 प्रतिशत की कमी आती है। यह मार्ग अफ़ग़ानिस्तान (जहां सीमा संघर्ष लगातार जारी हैं) को पूरी तरह से दरकिनार कर देता है और पाकिस्तान को पश्चिमी एशिया में चीन समर्थित व्यापार मार्गों के लिए एक प्रमुख ओवरलैंड गेटवे के रूप में स्थापित करता है। महत्वपूर्ण रूप से, पाकिस्तान ने इस मार्ग से भारतीय मूल के सामानों के पारगमन पर प्रतिबंध जारी रखा है।

मध्य गलियारा की संकल्पना

रूस पर कड़े पश्चिमी प्रतिबंधों और ईरान में जारी युद्ध के कारण, 'मध्य गलियारा' या 'ट्रांस-कैस्पियन इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट रूट' (TITR) यूरेशिया के सबसे महत्वपूर्ण और बहुचर्चित वैकल्पिक पारगमन मार्ग के रूप में उभरा रहा है। 4,000 km लंबा यह मल्टीमॉडल नेटवर्क पश्चिमी चीन को कज़ाकिस्तान, कैस्पियन सागर, दक्षिण काकेशस (अज़रबैजान और जॉर्जिया), काला सागर और तुर्की के माध्यम से पूर्वी यूरोप से जोड़ता है। वर्तमान आंकड़े स्पष्ट रूप

से इस मार्ग की बढ़ती प्रासंगिकता को दर्शाते हैं। 2024 में कैस्पियन सागर के पार मध्य गलियारे में माल ढुलाई की मात्रा में साल-दर-साल 63% की अभूतपूर्व वृद्धि हुई, जो 4.1 मिलियन टन तक पहुंच गई (रूस-यूक्रेन युद्ध से पूर्व यह केवल 500,000 टन थी)। अप्रैल 2026 में अस्ताना में आयोजित TITR की महासभा में कज़ाकिस्तान, चीन, अज़रबैजान, जॉर्जिया, तुर्की और यूरोपीय देशों के प्रतिनिधियों ने एक विस्तृत '2026 कार्य योजना' को मंज़ूरी दी। इसका मुख्य उद्देश्य परिवहन प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण, इलेक्ट्रॉनिक सीमा शुल्क डेटा विनिमय लागू करना और कंटेनर ट्रैफ़िक को बढ़ाना है। इसके परिणामस्वरूप 2026 की पहली तिमाही में ही कज़ाकिस्तान के माध्यम से 125 कंटेनर ट्रेनों का पारगमन हुआ, जो 2025 की तुलना में 34.4% अधिक है । वर्तमान भू-राजनीतिक परिदृश्य में 'मध्य गलियारा' बीजिंग और यूरोपीय बाज़ारों के मध्य सर्वाधिक तीव्र और सुगम व्यापारिक धमनी के रूप में प्रतिष्ठित हुआ है, जो पारंपरिक उत्तरी मार्गों की भौगोलिक दूरी को लगभग 2,500 किलोमीटर तक संकुचित कर देता है। मात्र 10 से 15 दिनों की पारगमन अवधि के साथ, यह नेटवर्क उन पुराने समुद्री मार्गों की तुलना में अत्यंत प्रभावी सिद्ध हो रहा है, जहाँ माल पहुँचने में 15 से 60 दिन का समय व्यतीत होता था। रूस को रणनीतिक रूप से दरकिनार करते हुए, यह गलियारा वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा को सुदृढ़ करने तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से उत्पन्न होने वाले व्यापारिक जोखिमों के न्यूनीकरण का एक अभूतपूर्व अवसर प्रदान करता है यद्यपि इस मार्ग की माल ढुलाई क्षमता में गुणात्मक वृद्धि दृष्टिगोचर हो रही है, तथापि मध्य गलियारे की कतिपय मौलिक संरचनात्मक और भू-भौतिकीय भेद्यताएं इसकी दीर्घकालिक स्थिरता एवं सामरिक प्रासंगिकता पर गंभीर प्रश्नचिह्न हैं।

इसके अतिरिक्त, चीन और रूस 'उत्तरी समुद्री मार्ग' (NSR) के विकास में तेजी ला रहे हैं। यह आर्कटिक मार्ग स्वेज़ नहर के माध्यम से जाने वाले पारंपरिक दक्षिणी मार्ग की तुलना में एशिया-यूरोप यात्रा को 30% से 40% तक छोटा कर देता है, जिससे ईंधन की भारी बचत होती है और यह अमेरिकी नाकेबंदी से पूरी तरह अछूता है। वास्तव में यह मार्ग चीन केBRI को आर्कटिक क्षेत्र में एकीकृत करते हुए ध्रुवीय रेशम मार्ग का निर्माण करता है। यह आर्कटिक गलियारा न केवल परिवहन समय को कम करता है, बल्कि चीन को मलक्का डिलेमा जैसी भौगोलिक कमजोरियों से भी सुरक्षा प्रदान करता है। रूस के साथ तकनीकी और सामरिक सहयोग के माध्यम से, चीन इस क्षेत्र में बर्फ तोड़ने वाले जहाजों और डिजिटल बुनियादी ढांचे में भारी निवेश कर रहा है। 'ध्रुवीय रेशम मार्ग' बीजिंग की उस दीर्घकालिक योजना का हिस्सा है जिसके तहत वह समुद्री वर्चस्व के लिए केवल हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर पर निर्भर नहीं रहना चाहता। अमेरिकी टैरिफ नीति और 'ऑपरेशन एपिक फ्यूरी' जैसी सैन्य कार्रवाइयों के बीच, यह सुरक्षित उत्तरी गलियारा वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को बनाए रखने के लिए चीन के लिए एक अनिवार्य सामरिक ढाल के रूप में प्रतिस्थापित करने का प्रयास है।

चीन की सामरिक दृष्टिकोण का रूपांतरण: भू-आर्थिक प्रभुत्व से सामरिक-रणनीतिक सहयोग एवं तकनीकीकरण

वर्तमान मध्य पूर्व के भीषण संकट ने बीजिंग की वैदेशिक कूटनीति के पारम्परिक प्रतिमानों में एक मध्य पूर्व के वर्तमान व्यापक संकट ने बीजिंग की विदेश नीति के पारंपरिक सिद्धांतों में एक युगांतरकारी बदलाव ला दिया है। वास्तव में चीन की 'बेल्ट एंड रोड पहल' (BRI) अपनी शुरुआत में मुख्य रूप से *"अर्थशास्त्र-प्रथम"* की धारणा से प्रेरित थी, परन्तु इन वर्तमान परिस्थितियों ने बीजिंग को विवश कर दिया है कि, केवल व्यापारिक प्रगाढ़ता और आर्थिक अंतर्निर्भरता ही BRI के सामरिक बुनियादी ढांचे और दीर्घकालिक हितों की रक्षा के लिए पर्याप्त नहीं हैं। वर्तमान मध्य पूर्व के भीषण संकट ने बीजिंग की वैदेशिक कूटनीति के पारंपरिक प्रतिमानों में एक युगांतरकारी बदलाव ला दिया है। इसके जवाब में, चीन अब अपनी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने के लिए मजबूत और बहुआयामी सुरक्षा साझेदारियों की आवश्यकता को प्राथमिकता दे रहा है। जहाँ 'बेल्ट एंड रोड पहल' (BRI) अपनी शुरुआत में मुख्य रूप से *"अर्थशास्त्र-प्रथम"* की अवधारणा से निर्देशित थी, वहीं अब बीजिंग इस यथार्थ को स्वीकार करने हेतु विवश हुआ है कि केवल वाणिज्यिक प्रगाढ़ता और आर्थिक अंतर्निर्भरता BRI के रणनीतिक बुनियादी ढांचे

एवं दीर्घकालिक संबंधों को सुरक्षित रखने में अक्षम हैं।

चीन का यह रणनीतिक रूपांतरण अब 'ग्लोबल सिक्योरिटी इनीशिएटिव' (GSI) के माध्यम से प्रकट हो रहा है, जहाँ वह मध्य एशिया और दक्षिण एशिया में स्वयं को एक प्रमुख सुरक्षा गारंटर के रूप में स्थापित कर रहा है। बीजिंग की हाल ही में जारी पंद्रहवीं पंचवर्षीय योजना (2026-2030) भी इस सुरक्षा-उन्मुख दृष्टिकोण को पुष्ट करती है, जो BRI को राष्ट्रीय सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखलाओं के लचीलेपन के साथ एकीकृत करने पर बल देती है। यह बदलाव यह स्पष्ट करता है कि चीन अब केवल आर्थिक निवेश के माध्यम से नहीं, बल्कि '2+2 सुरक्षा कूटनीति' और निजी सुरक्षा कंपनियों के एकीकरण के माध्यम से अपने वैश्विक रसद नेटवर्क को सुरक्षित करने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। इसी प्रकार यूक्रेन के साथ दीर्घकालिक सैन्य संघर्ष में अपनी रणनीतिक शक्ति के क्षरण के कारण रूस, जो ऐतिहासिक रूप से मध्य एशियाई क्षेत्र का मुख्य सुरक्षा स्तंभ रहा है, वर्तमान में अपनी संपूर्ण सामरिक क्षमता का प्रयोग करने में असमर्थ सिद्ध हो रहा है। इस परिस्थिति ने यूरेशियाई हृदयस्थल में एक गंभीर *"सुरक्षा शून्यता"* को जन्म दिया है, जिसे बीजिंग अब एक वैकल्पिक और सक्षम सुरक्षा भागीदार के रूप में प्रतिस्थापित होकर तीव्रता से भरने का प्रयास कर रहा है।

इसी प्रकार यूरेशिया और मध्य पूर्व के अस्थिर क्षेत्रों से गुजरने वाले BRI मार्गों पर चीनी संपत्तियों और नागरिकों की सुरक्षा एक प्रमुख चुनौती बन गई है। इस जोखिम को कम करने के लिए, चीन ने 'निजी सुरक्षा कंपनियों' (PSCs) की तैनाती में व्यवस्थित वृद्धि की है । ओपन-सोर्स डेटा के अनुसार, वर्तमान में मध्य पूर्व, मध्य एशिया और दक्षिण एशिया सहित वैश्विक स्तर पर कम से कम 32 चीनी PSCs सक्रिय रूप से कार्य कर रही हैं ।

बीजिंग का कूटनीतिक दृष्टिकोण एवं रणनीतिक प्रतिक्रिया

समकालीन वैश्विक कूटनीतिक मंच पर, चीन 2026 के इस विस्फोटक अमेरिका-ईरान संघर्ष को अमेरिका द्वारा संचालित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की अस्थिरता और आक्रामक स्वरूप को उजागर करने हेतु एक प्रभावी उपकरण के रूप में प्रयुक्त कर रहा है। चीन ने संप्रभु भौगोलिक सीमाओं पर अमेरिका-इज़राइल गठबंधन द्वारा किए गए हमलों की तीखी आलोचना की है। चीनी विदेश मंत्रालय ने राजनयिक वार्ताओं के मध्य नेतृत्व की हत्या एवं *"शासन परिवर्तन"* की अमेरिकी प्रवृत्तियों को *"जंगल राज"* की संज्ञा देते हुए इसे ईरानी संप्रभुता का क्रूर उल्लंघन निरूपित किया है। चीनी सामरिक विशेषज्ञों एवं खुफिया विश्लेषणों के अनुसार, वाशिंगटन प्रत्यक्ष सैन्य अभियानों के साथ-साथ ईरान पर दबाव बढ़ाने हेतु *"युद्धक्षेत्रों के पृथक्करण"* की एक जटिल निवारण रणनीति का अनुसरण कर रहा है। इस अमेरिकी सामरिक नीति का मूल उद्देश्य तेहरान और उसके क्षेत्रीय छद्म समूहों—विशेषकर हिज़्बुल्लाह एवं हूती—की मारक क्षमता को पंगु बनाना तथा युद्ध के स्थापित मानदंडों को पुनर्संयोजित करना है। चीनी नेतृत्व का यह सुदृढ़ मत है कि ट्रम्प प्रशासन का मूल रणनीतिक लक्ष्य 2021 में हस्ताक्षरित "चीन-ईरान व्यापक रणनीतिक साझेदारी" के विखंडन में निहित है। इसके माध्यम से अमेरिका का प्रयास बीजिंग को डॉलर-मुक्त एवं किफायती ईरानी ऊर्जा संसाधनों से वंचित करना तथा मध्य पूर्व में BRI के विस्तार को अवरुद्ध करना है। इसके प्रत्युत्तर में, चीनी वाणिज्य मंत्रालय ने ईरानी तेल का आयात करने वाली निजी चीनी रिफाइनरियों पर आरोपित अमेरिकी एकतरफा प्रतिबंधों को स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया है। चीन स्वयं को ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन के माध्यम से *"ग्लोबल साउथ"* के एक विश्वसनीय सुरक्षा स्तंभ के रूप में प्रतिस्थापित कर रहा है, जो अमेरिका की अस्थिरता-प्रेरित नीतियों के सम्मुख एक स्थिर विकल्प प्रस्तुत करता है।

निष्कर्ष

वर्तमान अमेरिका-ईरान संघर्ष वैश्विक व्यवस्था के लिए एक निर्णायक मोड़ है, जिसने 'सौम्य वैश्वीकरण' को 'आर्थिक

शस्त्रीकरण' और 'संरचनात्मक विखंडन' के युग में बदल दिया है। इस संकट ने चीन की बेल्ट एंड रोड पहल (BRI) के भू रणनीतिक सीमाओं को उजागर किया है। अब बीजिंग यह स्वीकार कर चुका है कि केवल आर्थिक अंतर्निर्भरता रणनीतिक बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके परिणामस्वरूप, चीन अब अपनी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं की सुरक्षा हेतु वाणिज्यिक प्रगाढ़ता के स्थान पर सुदृढ़ और बहुआयामी सुरक्षा भागीदारियों को प्राथमिकता देने पर बल दे रहा है। बीजिंग अपनी महत्वाकांक्षी 'बेल्ट एंड रोड पहल' (BRI) के अंतर्गत नवीन परन्तु अनिश्चित भू-आर्थिक रणनीतिक प्रतिमानों को त्वरित गति से अंगीकार कर रहा है। फारस की खाड़ी एवं ईरानी भू-भाग पर अपनी पारम्परिक निर्भरता के शमन हेतु, चीन अब कैस्पियन पार 'मध्य गलियारे' तथा रूसी संघ के माध्यम से प्रसारित उत्तरी पारगमन मार्गों में सघन निवेश सुनिश्चित कर रहा है।

इस नए सामरिक वास्तविकता ने चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) को एक नए अर्थ भी प्रदान किया हैं। प्रारंभिक चरण में BRI को मुख्यतः व्यापार, अवसंरचना निवेश और क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने वाली आर्थिक परियोजना के रूप में प्रस्तुत किया गया था। किंतु पश्चिम एशिया, लाल सागर और हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ती अस्थिरता ने चीन के नीति-निर्माताओं को यह एहसास कराया है कि केवल समुद्री मार्गों पर निर्भर रहना दीर्घकालिक राष्ट्रीय हितों के लिए जोखिमपूर्ण है। चीन की ऊर्जा आवश्यकताओं का बड़ा भाग पश्चिम एशिया से आयातित तेल और गैस पर आधारित है, जो मुख्यतः होर्मुज और मलक्का जैसे समुद्री मार्गों से होकर चीन पहुँचते हैं। अतः यदि इन मार्गों में व्यवधान उत्पन्न होता है, तो चीन की आर्थिक वृद्धि, औद्योगिक उत्पादन और ऊर्जा सुरक्षा गंभीर संकट में पड़ सकती है। इसी कारण BRI अब केवल एक विकास परियोजना नहीं रह गई है, बल्कि यह चीन की व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति (Grand Strategy) का अभिन्न अंग बन चुकी है। इस प्रकार निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि होर्मुज जलडमरूमध्य संकट ने न केवल क्षेत्रीय अस्थिरता को जन्म दिया है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में एक मौलिक और संरचनात्मक परिवर्तन को भी उजागर किया है।

इसने वैश्विक शक्तियों के सम्मुख यह निर्विवाद सत्य सिद्ध कर दिया है कि समुद्री मार्गों की सुरक्षा अब पूर्ववत सुनिश्चित या स्वतः उपलब्ध नहीं मानी जा सकती। परिणामस्वरूप, चीन के लिए बेल्ट एंड रोड पहल (BRI) एक साधारण वैकल्पिक संपर्क परियोजना की सीमाओं को लांघकर ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला संरक्षण तथा राष्ट्रीय शक्ति के संवर्धन एवं संरक्षण का एक अनिवार्य साधन बन गया है। इस अभूतपूर्व संकट के आलोक में, चीन की भू-रणनीतिक प्राथमिकताएं अब 'समुद्री निर्भरता' से हटकर 'महाद्वीपीय सुदृढ़ीकरण' की ओर स्थानांतरित हो गई हैं। हॉर्मूज और मलक्का जैसे चोक-पॉइंट्स पर अमेरिकी नौसैनिक वर्चस्व ने बीजिंग को अपनी रणनीतिक भेद्यता का एहसास कराया है, जिससे BRI अब उसकी उत्तरजीविता का आधार बन चुका है। दूसरे शब्दों में, वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों और 'ऑपरेशन एपिक फ्यूरी' जैसी सैन्य कार्रवाइयों के बीच, BRI को केवल एक आर्थिक निवेश पहल के रूप में नहीं, बल्कि चीन की राष्ट्रीय सुरक्षा तथा उसकी दीर्घकालिक भू-राजनीतिक ग्रैंड स्ट्रेटजी के केंद्रीय स्तंभ के रूप में परिवर्तित कर दिया है।

संदर्भ सूची

1. Morgenthau, Hans J. *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*. Alfred A. Knopf, 1948, pp. 85-92.
2. Waltz, Kenneth N. *Theory of International Politics*. Addison-Wesley, 1979, pp. 116-123.
3. Mackinder, Halfords J. "The Geographical Pivot of History". *The Geographical*

Journal, vol. 23, no. 4, 1904, pp. 421-437.

4. Farrell, H., & Newman, A. L. "Weaponized Interdependence: How Global Economic Networks Shape State Coercion". *International Security*, vol. 44, no. 1, 2019, pp. 42-79.
5. Rolland, Nadège. *China's Eurasian Century? Political and Strategic Implications of the Belt and Road Initiative*. NBR, 2020, pp. 145-160.
6. Pant, H. V., & Sharma, R. "India's Strategic Autonomy in an Era of Secondary Sanctions: The Chabahar Dilemma". *The Hindu*, National Edition, 18 May 2025, p. 10.
7. World Bank Group. *Trade Corridors in Transition: The Middle Corridor and Eurasian Connectivity*. Report No. 18294-ECA, 2026, pp. 34-41.
8. Hillman, Jonathan E. *The Digital Silk Road: China's Quest to Wire the World and Win the Future*. Harper Business, 2021, pp. 45-78.
9. Huang, Yanzhong. "The Health Silk Road: How China Adapts the Belt and Road Initiative to the COVID-19 Era." *Council on Foreign Relations Report*, 2022, pp. 12-24.
10. Rolland, Nadège. "China's Digital Silk Road and Global Tech Dominance." *Journal of Contemporary China*, vol. 29, no. 124, 2020, pp. 580-595.
11. Lancaster, K., & Rubin, M. "Mapping China's Health Silk Road." *Council on Foreign Relations - Policy Innovation Memorandum*, 2021, pp. 3-9.